

सशक्त अंधोसंरचना ही प्रभावी न्यायप्रणाली की नींव

सुविधा ● तहसील बिल्हा में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन का चीफ जस्टिस ने किया लोकार्पण

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में न्यायिक अधोसंरचना में वृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए एवं आमजन के लिए बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बिल्हा तहसील में नवीन सिविल कोर्ट भवन लोकार्पण किया। इस अवसर पर जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी पोर्टफोलियो न्यायाधीश जिला बिलासपुर, जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास, जस्टिस रविन्द्र कुमार उपस्थिति रही हैं।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने न्याय की प्रभावी पहुंच आमजन तक स्थापित किये जाने में न्यायिक अधोसंरचना के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सशक्त अंधोसंरचना ही प्रभावी न्यायप्रणाली की आधारशिला होती है। छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में बुनियादी न्यायिक अधोसंरचना स्थापित होने से न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता बढ़ने के साथ-साथ आमजन को निष्पक्ष एवं कुशल न्याय शीघ्र, सरल एवं सुलभ हो सकेगा। नवीन सिविल



उद्घाटन के अवसर पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व अन्य न्यायिक अधिकारी। ● नईदुनिया

न्यायालय भवन बिल्हा की हरियाली, वातावरण एवं स्वच्छता के साथ-साथ न्यायालय कक्ष, सुविधाजनक प्रतीक्षालय, शिशु देखभाल कक्ष अभियोजन कार्यालय, सुरक्षित बंदीगृह एवं उपलब्ध सुविधाएं की प्रशंसा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि यह भवन छत्तीसगढ़ के अन्य जिला न्यायालयों के लिये मिसाल साबित होगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक संस्थाओं में बुनियादी एवं आधारभूत सुविधा उपलब्ध किये जाने पर जोर दिया जाता रहा है एवं उनकी प्राथमिकता ऐसी व्यवस्था किये जाने की है कि छत्तीसगढ़ के सभी न्यायिक

संस्थाओं में सर्वसुविधायुक्त भवन हो, जिससे आधारभूत संसाधन उपलब्ध रहे। बिल्हा में नवीन सिविल कोर्ट भवन, समय की जरूरत थी। बिल्हा में नवीन न्यायालय भवन निर्माण से स्थानीय नागरिकों को न्याय तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगी। लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के स्वागत भाषण से हुई और समापन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। कार्यक्रम के पश्चात न्यायालय भवन प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता, रजिस्ट्रार

आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण है भवन

यह भवन न केवल भौतिक रूप से सुसज्जित है, बल्कि इसमें डिजिटल कोर्ट, वकीलों के लिए आधुनिक कक्ष, अस्पताल, एटीएम तथा प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। इस अवसर पर चीफ जस्टिस ने उपस्थित न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्तागण को दिशानिर्देश दिया कि सुविधायुक्त अधोसंरचना व आधुनिक तकनीकी का उपयोग पक्षकारों को सुविधापूर्ण वातावरण में शीघ्र एवं गुणवत्तायुक्त न्याय प्रदान किए जाने के लिए किया जाए।

जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं समस्त न्यायिक अधिकारी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बिलासपुर, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बिल्हा, संभाग आयुक्त, पुलिस आयुक्त, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य प्रशासनिक, पुलिस, एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, पीपीएस, प्रोटोकाल अधिकारी, अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारी शामिल थे।

पक्षकारों की समस्याओं को सुविधापूर्ण वातावरण में करें निराकृत

चीफ जस्टिस द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के दूरस्थ जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायलयों का भ्रमण कर न्यायिक अधोसंरचना एवं आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने से पक्षकारों, अधिवक्ता, न्यायिक कर्मचारी एवं अधिकारियों को होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दूरदर्शिता पूर्ण एवं सकारात्मक सोच के भागीरथ प्रयास किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में न्यायिक अधोसंरचना से अभूतपूर्ण विकास का कार्य हो रहा है। इससे अधिकारी एवं कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि होने के साथ पक्षकारों को सुविधायुक्त वातावरण शीघ्र न्याय प्राप्त करने की परिकल्पना साकार हो रही है एवं बिल्हा का नवीन न्यायालय भवन का निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता के उच्चतम मानकों के अनुरूप पूर्ण हो सका है।